Demand to open more Jan Aushadhi Kendras in the rural areas of Western Uttar Pradesh

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीब लोगों को सस्ती दर पर जीवनरक्षक जेनरिक दवाएँ एवं मेडिकल उपकरण उपलब्ध कराने हेतु जन-औषधि केन्द्र खोलने का निर्णय किया है, जिसका मैं स्वागत करता हूँ। वर्ष 2008-09 में आरंभ की गई इस योजना के तहत देश में करीब 3,195 जन-औषधि केन्द्र निजी और गैर-सरकारी संगठनों ने स्थापित किए, जिनमें उत्तर प्रदेश में 475 केन्द्र खुले। लेकिन मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ गरीब सबसे अधिक है, वहाँ उचित मात्रा में जन-औषधि केन्द्र नहीं खुले हैं तथा जो केन्द्र चल रहे हैं, उनमें अक्सर दवाओं का अभाव रहता है।

अतः मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा तथा सरकार से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में, प्रत्येक विकास खंड में कम से कम दो जन-औषधि केन्द्र खोले जाएँ तथा उन पर समय पर सभी दवाएँ उपलब्ध हों, ताकि गरीब जनता को इसका पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि देश की आबादी का अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो गरीब है तथा उसे समय पर दवाएँ उपलब्ध न होने के कारण वह दम तोड़ देता है। मैं आपके माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आबादी का घनत्व अधिक होने के कारण वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अधिक जन-औषधि केन्द्र खोलने का निवेदन करता हूँ।

Demand to take stringent steps to curb corruption and prevalence of black money in medical admissions

DR. R. LAKSHMANAN (Tamil Nadu): Sir, after introduction of NEET, the Government has allowed many private colleges to increase the tuition fees to offset the loss of capitation fees. The tuition fee is fixed arbitrarily to cater to only rich or super-rich students. How can the Government allow this when the Supreme Court had made NEET mandatory for even private colleges and deemed universities to ensure medical admissions to the deserved? This is an injustice to the poor meritorious students.

Other than the prescribed tuition fee fixed by the Government, the private medical colleges are collecting additional amount to ensure seats to the poor-ranked rich students. This again leads to corruption and prevalence of black money in admissions even after the implementation of NEET.

There are only 60,000-odd MBBS seats in India. The tuition fees for the Government quota in private colleges is fixed at ₹ 4 lakhs for MBBS whereas it is roughly ₹ 1 crore in the private universities. The high fees charged by most private universities is forcing thousands of poor students with NEET scores to forego seats and allowing poor performers with money to get admissions, thereby lowering the